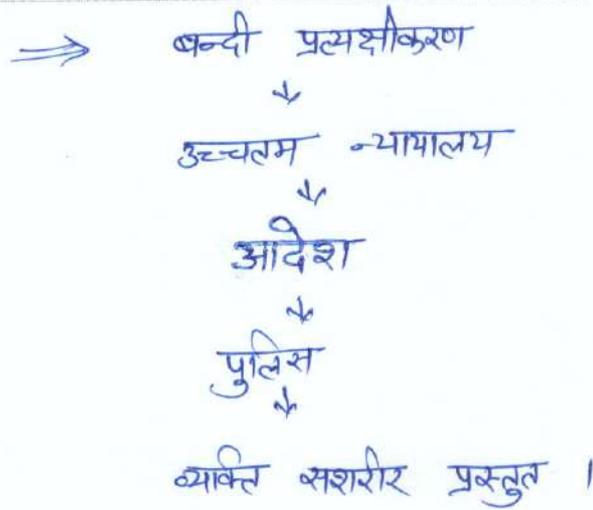


⇒ अतः 44 वें संविधान संशोधन के बाद सम्पत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार हो गया। जिसके लिए अब अनुच्छेद-32 का प्रयोग नहीं किया जा सकता।

संवैधानिक उपचारों का अधिकार →

1. अनुच्छेद-32 को डॉ. अम्बेडकर के द्वारा संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया क्योंकि अनुच्छेद-32 का दोहरा महत्व है। यह अन्य अधिकारों की प्राप्ति तक मूल अधिकार है इसलिए राज्य के द्वारा निर्मित विधि से इसे समाप्त नहीं किया जा सकता।
2. अनुच्छेद-32 अन्य मूल अधिकारों को क्रियान्वित करता है।
3. उच्चतम न्यायालय के द्वारा विभिन्न प्रकार की याचिका प्रदान की जाती है, जिसमें बन्दी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार पृच्छा, प्रतिषेध, उल्लेख।



परमादेश - उच्चतर अधिकारी के द्वारा अपने कमिष्ठ अधिकारी को आदेश देना (सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति को)।

परमादेश निजी पद पर बैठे व्यक्ति के विरुद्ध नहीं दिया जा सकता।

⇒ राष्ट्रपति / राज्यपाल सार्वजनिक पद पर होते हुए भी इन्हें रिट जारी नहीं किया जा सकता क्योंकि वह पद पर होते हुए भी कार्य के प्रति जिम्मेदार नहीं होते।

4. सामान्यतः उच्चतम न्यायालय निजी पदाधिकारियों के विरुद्ध परमादेश नहीं देता और राष्ट्रपति और राज्यपाल संवैधानिक और सार्वजनिक

पद होने के बावजूद भी परमादेश के दायरे में नहीं आते।

5. दूर ही में न्यायिक सक्रियता के कारण उच्चतम न्यायालय ने सतत परमादेश का विचार भी अपनाया है।

6. 1996 में विनीत नारायण वाद में उच्चतम न्यायालय ने सी.बी.आई. के डायरेक्टर को यह परमादेश दिया कि दबाला मामले में भ्रष्टाचार की जांच हेतु निदेशक सीधे उच्चतम न्यायालय को रिपोर्ट दें और इस मामले की निरन्तर निगरानी हेतु उच्चतम न्यायालय ने CBI के निदेशक को बार-बार परमादेश दिया।

7. शक्ति प्रवक्त्रण के कारण पहले न्यायालय स्पीकर को परमादेश देने से बचते थे लेकिन हाल के वर्षों में स्पीकर को भी परमादेश दिए गए हैं और तमिलनाडु के

राज्यपाल को भी उच्चतम न्यायालय के द्वारा परामर्श दिया गया है।

8. अधिकार पृच्छा निजी पद के लिए लागू नहीं होता।

राज्यपाल को भी उच्चतम न्यायालय के

द्वारा परामर्श दिया गया है।

अधिकार पृच्छा निजी पद के लिए लागू नहीं होता।